the implementation of these provisions in the past. These matters are being discussed between the managements and the unions in the JBCCI.

**American Business Interests in India**

848. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that America's business interest in India is growing; and

(b) what are the troublesome issues identified which are putting pressures for not widening the depth of the commercial relationship further between the two countries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) Various issues which need to be addressed in the context of growing commercial relations are discussed bilaterally as well as multilaterally but such issues are not expected to come in the way of increasing commercial relations between India and USA.

**कजाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध सुदृढ़ करना**

849. **श्री प्रमोद महाजनः**
**श्री गोविन्दराव आदिकः**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कजाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैंः

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा उस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह भी सच है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्)**: (क) से (ङ) जी, हां। सरकार कजाकिस्तान के साथ एक सी॰ आई॰ एस॰ देश के रूप में भारत के व्यापार संवर्धन के लिए सतत आधार पर उपाय कर रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की गुंजाइश है। सहयोग के क्षेत्र ये हैं — संयुक्त व्यापारिक उद्यमों, तीसरे देशों को निर्यात हेतु संयुक्त उद्यमों आदि सहित संयुक्त उद्यमों, परस्पर पूंजीनिवेश का संवर्धन, बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सहयोग का संवर्धन और प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रावधान।

भारत सरकार द्वारा द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए किए गए कुछ निश्चित उपाय नीचे दिए जा रहे हैं:—

1. कजाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना।
2. व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के संबंध में नया द्विपक्षीय ढांचा करार करना।
3. वाणिज्यिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग बढ़ाने के लिए अन्तः सरकारी द्विपक्षीय संयुक्त-आयोगों का गठन।
4. प्रतिव्यापार, खेप निर्यात बढ़ाना और भाण्डागारों की स्थापना।
5. संयुक्त उद्यमों का संवर्धन।
6. भारत सरकार का 20 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देना। कजाकिस्तान को ऋण की दूसरी किश्त के लिए उदारीकृत ऋण शर्तें।
7. कजाकिस्तान सहित सी॰आई॰एस॰ देशों के साथ भारतीय व्यापार के लिए और अधिक अर्थक्षम पारगमन मार्गों का पता लगाना और उनका विकास करना।
8. द्विपक्षीय हवाई यातायात करार करना और सीधी उड़ाने आरंभ करना, एयरकार्गो यातायात का संवर्धन।
9. अन्य बातों के अलावा, प्रतिनिधि कार्यालय खोलकर, आई॰टी॰पी॰ओ॰ को प्रदर्शनियां आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित करके सीधे

व्यापारी-स्तर पर सम्पर्क बढ़ाना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना।

10. सरकारी तथा व्यापारी हस्तियों का उच्चस्तरीय आदान-प्रदान।

(च) तथा (छ) यह बात सच है कि अर्थक्षम पारगमन मार्ग का अभाव द्विपक्षीय व्यापार में एक बाधा है। इस समस्या के निराकरण के लिए भारत सरकार ने विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के एक ऐसे — अध्ययन दल का गठन किया था जिसे ईरान और मध्य एशियाई गणराज्यों (सी० ए० आर०) का दौरा कर सी० ए० आर० के लिए संभावित पारगमन मार्गों की जांच का काम सौंपा गया था। इस दल ने यह निष्कर्ष दिया है कि कजाकिस्तान के लिए बरास्ता ईरान वाला मार्ग विश्वसीनय, तीव्र और किफायती साबित होगा।

इस दिशा में भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच होने वाले एक त्रिपक्षीय करार के लिए बातचीत चल रही है।

**Violation of Rules Governing WTO by Pakistan**

850. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether India has lodged any complaint with Pakistan regarding its discrimination in violation of the rules govering the World Trade Organisation;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether Government have approached the Government of Pakistan to grant it the most favoured-nation status trade; if so, what are the details in this regard; and

(d) what has been Pakistan Government's response in the matter raised in parts (a) and (c) above?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) Government of India has been requesting the Government of Pakistan at various levels to restore Most Favoured Nation (MFN) treatment to Indian exports. Recently the Government of India has again formally drawn the attention of the Government of Pakistan to this matter and has urged an early resolution in accordance with the obligations of Pakistan under GATT/WTO.

(d) the response of the Government of Pakistan is awaited.

**Aggregate Measurement of Support for Wheat, Cotton and Rice**

851. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what was the Aggregate Measurement of Support (AMS) during the Uruguay Round (1986—89) for wheat, cotton and rice;

(b) what was the International Reference Price (IRP) of these crops at the time;

(c) what percentage of the AMS remained of the International Reference Price during the reference years; and

(d) the details of the negative/positive support on these crops during the reference years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) The concept of AMS used in the Uruguay Round Agreement on Agriculture is a negotiated concept designed to measure the trade distorting domestic support given to agriculture by member counties of GATT. It does not take into account a large variety of support measures for the agricultural sector. Under this concept AMS is the aggregate of product specific support and non-product specific support.

AMS on a product specific basis for wheat, cotton and rice receiving market price support during the reference period i.e. 1986-87 to 1988-89 was calculated as under by using the gap between a fixed international reference price and the applied administered price of the